दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 30 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 32

न्यायमूर्ति बोबड़े होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश

» 18 नंवबर को लेंगे शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे को मंगलवार को देश का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

कानून मंत्रालय ने मंगलवार को न्यायमूर्ति बोबडे की देश के नये प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति बोबडे करीब 17 महीने प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने देश के नये प्रधान न्यायाधीश पद पर न्यायमूर्ति बोबडे की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किये। न्यायमूर्ति बोबडे की नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के स्थान पर की गयी है जो 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति बोबडे 23 अप्रैल 2021 तक देश के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्थापित परपंरा के अनुरूप पिछले सप्ताह ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबडे की नियुक्ति की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति बोबडे ने 1978 में महाराष्ट्र बार काउन्सिल में पंजीकरण कराने के बाद बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में वकालत शुरू की। उन्हें 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किया गया। न्यायमूर्ति बोबडे की 29 मार्च 2000 को बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हुयी। वह 16 अक्टूबर 2012 को मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 12 अप्रैल 2013 को पदोन्नति देकर उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया।

कौन है बोबड़े

जस्टिस बोबड़े मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में 1 साल तक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके अलावा 12 वर्ष तक बॉम्बे हाइकोर्ट में जज भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आधार, पर्यावरण और धर्म से जुड़ी कई मामलों में फैसले सुनाया है। अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई करने वाले पांच जजों की पीठ में जस्टिस बोबड़े भी शामिल हैं। वह आधार के अधिकार पर सुनाए गए तीन बेंच के जजों का हिस्सा रहे हैं। तीन सदस्यों की इस पीठ में जस्टिस बोबड़े के अलावा जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस नागप्पन भी थे। इस ऐतिहासिक फैसले में पीठ ने आधार के बिना किसी भी भारतीय को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित न किए जाने का फैसला सुनाया। 2016 में दिल्ली-एनसीआर में तीन विद्यार्थियों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर भी जस्टिस बोबड़े ने फैसला सुनाया था जिसमें पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस बेंच में जस्टिस बोबड़े के अलावा जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एके सिकरी भी थे।

आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल हैं मोदी व कोहली

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर की कई बड़ी हस्तियां आतंकियों के निशाने पर हैं। इसका खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक खुफिया दस्तावेज में हुआ है। आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को निशाना बना सकते हैं।

खुफिया दस्तावेज के अनुसार ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इस संगठन ने एक हिटलिस्ट तैयार की है जिसे एनआईए को भेजा गया है। इस सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सरसंघ संचालक मोहन भागवत, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा महासचिव राम माधव, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम भी शामिल हैं। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार इस खुलासे से साफ हो गया है कि पाकिस्तान एक और नापाक चाल चल रहा है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करने के बाद से पाकिस्तान काफी बौखला गया है। वह लगातार इसी कोशिश में हैं कि किस तरह से वह भारत पर आतंकी हमले करे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में वह नहीं चाहता कि किसी आतंकी संगठन के साथ उसका नाम जुड़े। यही वजह है कि उसने अपने यहां से आतंकियों को भेजकर संगठन को नया नाम दिया है।

नक्सलवादी घटनाओं में 9 साल में गई 749 लोगों की जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले नौ सालों के दौरान दस राज्यों में नक्सली हिंसा में 3700 से अधिक लोग मारे गए हैं, इनमें सबसे अधिक जान छत्तीसगढ़ में गई।

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाकपा (माओवादी) देश में विभिन्न वाम चरमपंथी संगठनों में सबसे ताकतवर संगठन है और वह 88 फीसदी से अधिक हिंसक घटनाओं एवं फलस्वरूप होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'बढ़ते नुकसान के बीच भाकपा (माओवादी) अंतर-राज्यीय सीमाओं पर नए क्षेत्रों में अपने पांव पसारने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।' रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से दस राज्यों में हिंसा की 10,660 घटनाओं में 3,749 लोगों की जाने गई हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 से 2018 के बीच माओवादियों द्वारा अंजाम दी गई 3769 हिंसक घटनाओं में 1370 लोगों की मौत हुई। वहीं झारखंड में वाम चरमपंथ की 3,358 हिंसक घटनाओं में 997 लोग मारे गए जबकि बिहार में उसी दौरान 1526 ऐसी ही हिंसक वारदातों में 387 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दस नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं।

अनाथ व दिव्यांगों के कल्याण पर खर्च करें सीएसआर: कोविंद

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारोबारी कंपनियों को सुझाव दिया कि वे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनाथ और दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए अधिक राशि खर्च करें।

यहां विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कंपनियों को सुझाव दिया है कि वे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनाथ और दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए अधिक राशि खर्च करें। उन्होंने कहा कि सीएसआर गतिविधियों के जरिये विकास की चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान ढूंढे जा सकते हैं। कंपनी कानून, 2013 के तहत सीएसआर प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से लागू हुए हैं। इस कानून के तहत कुछ निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत एक वित्त वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2014-15 से कंपिनयां हर साल सीएसआर पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती हैं। समाज कल्याण गतिविधियों पर खर्च करने के लिए संसाधन, इच्छाशक्ति और रूपरेखा अहम होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हमें किसकी अधिक मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने सुझाव दिया कि अनाथों और दिव्यांगों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि 2030 तक प्रत्येक अनाथ की देखरेख की जा सकेगी। अब से राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार हर साल दो अक्टूबर को दिए जाएंगे।

राष्ट्रगान के दौरान महिला सुरक्षाकर्मी घायल

दिल्ली में आज राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां सुरक्षा में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी राष्ट्रगान बजने के दौरान गिरकर घायल हो गई। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मानवीयता का परिचय देते हुए मंच से उतरकर महिला पुलिस कर्मी से मुलाकात की। महिला पुलिस कर्मी विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार समारोह के दौरान मंच के आगे खड़ी थीं।

सीएसआर के तहत गरीब, पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बढ़ाए कंपनियां: सीतारमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय कंपनियों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करने की अपील की है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही सीतारमण ने पिछले साल सीएसआर गतिविधियों पर करीब 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास के लिये काफी प्रासंगिक है। उन्होंने यहां पहले राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार वितरण के लिए राजधनी में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में ब्त् के क्षेत्र में काफी काम देखने को मिलते हैं. वहीं छत्तीसगढ़, ओड़िशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को भी सीएसआर के जरिये समर्थन की जरूरत है। इस मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को केवल संपत्ति सृजित करने के लिये सम्मानित नहीं किया जा रहा बल्कि समाज को सीएसआर के नाम पर वापस दिये जाने के लिये सम्मानित किया जा रहा है। सीएसआर के तहत लाभ का एक निश्चित हिस्सा समाज को देना है और इसको लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कंपनी कानून के तहत कुछ लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2 प्रतिशत कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर खर्च करने की जरूरत होती है।

इराक के कर्बला में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हमले में 18 लोगों की मौत

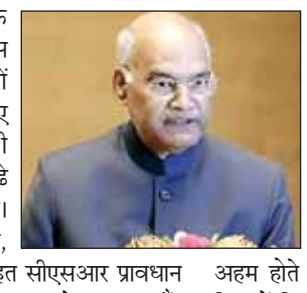

बगदाद। इराकी सुरक्षाबलों ने शिया समुदाय के पवित्र शहर कर्बला में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलायीं जिससे 18 लोगों की मौत हो गयी और कई घायल हो गए। सुरक्षाबल सादे कपड़ों में थे और उन्होंने नकाब लगा रखे थे।सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इराक में इस महीने के शुरू से ही प्रदर्शन हो रहे हैं और यह अब तक का सबसे घातक हमला था।इराक के नागरिकों ने लगातार पांचवें दिन सड़कों पर प्रदर्शन किया।

विज्ञापन के जरिए वकालत करने वालों पर बार काउंसिल सख्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने विज्ञापनों के जरिए वकालत का काम करने वाले पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई की है। काउंसिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑटो रिक्शा सहित परिवहन के अन्य स्थानीय साधनों पर विज्ञापन के माध्यम से वकालत का काम करने के लिए कई अधिवक्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन वकीलों को बार काउंसिल द्वारा लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस तरह के विज्ञापन जारी करना अधिवक्ता अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है। बीसीडी ने अधिवक्ता अधिनियम के तहत इन वकीलों को कदाचार के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। बीसीडी अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा कि कुछ वकील विज्ञापन जारी करके कानूनी पेशे को बदनाम कर रहे हैं, इसपर रोक है और यह अनैतिक भी है। बीसीडी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार एक अधिवक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य या विज्ञापन नहीं करेगा।

अनंतनाग में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

» दो फरार होने में कामयाब

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर में सुरक्षाबलों ने जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जबकि दो आतंकवादी भागने में कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी अनंतनाग में मारे में ट्रक ड्राइवर की हत्या में शामिल रहा है। सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद सेना ने सर्च अभियान शुरू किया था।

आतंकियों ने खुद को सुरक्षाबलों से घिरता हुआ देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने गोलियां चलाई जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। मंगलवार को यूरोपियन सांसद जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे के पहले सोमवार को आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यह चौथा मौका है जब आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या की हो।

बता दें कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से कश्मीर में यह चौथी घटना है जब किसी ट्रक चालक की हत्या की गई है। इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबेहरा के कानिलवान इलाके में शाम को आतंकवादियों ने ट्रक ड्राइवर नारायण दत्त पर गोलियां चलाईं। दत्त की मौके पर मौत हो गई। दत्त उधमपुर के कटरा का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दो अन्य ड्राइवरों की जान बचाई। पुलिस के अनुसार सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की धर-पकड़ के लिए अभियान जारी है।

दत्त की हत्या के पहले ट्रक ड्राइवरों और बाहरी लोगों पर आतंकवादियों द्वारा कई हमले किए गए हैं। आतंकवादियों ने 24 अक्तूबर को शोपियां जिले में दो गैर-कश्मीरी ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी थी। एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक सहित दो आतंकवादियों ने 14 अक्तूबर को राजस्थान के नंबर वाले एक ट्रक के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शोपियां जिले में एक बाग मालिक पर हमला किया था। दो दिनों बाद पंजाब के सेब व्यापारी चरणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसी दिन पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के एक ईट भट्ठा श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा

» सोनिया ने दो नवंबर को बुलाई बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी दो नवंबर को पार्टी के महासचिवों एवं प्रभारियों की बैठक बुलाई है जिसमें अर्थव्यवस्था में सुस्ती, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की बुरी हालत और बेरोजगारी जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा।सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में महाराष्ट्र एवं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों और इसके बाद की राजनीतिक स्थिति तथा कुछ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।यह बैठक उस वक्त हो रही है जब कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर 'विफलता' को लेकर पांच से 15 नवंबर के बीच मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।सूत्रों का कहना है कि सोनिया की अध्यक्षता में शनिवार शाम होने वाली इस बैठक में पांच से 15 नवंबर के बीच होने जा रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी रणनीति पर चर्चा होगी।हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद इस तरह की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले, गत 25 अक्टूबर को कांग्रेस के विशेष समूह की बैठक हुई थी।दरअसल, महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को कुल 98 सीटें मिलीं, जिनमें राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुईं। वहीं भाजपा को 105 और शिवसेना ने 56 सीटें मिलीं।हरियाणा में भाजपा ने 40 और जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिलीं। कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को देखते हुए इन दोनों राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

स्वदेशी फाइटर जेट बनाने की तैयारी में वायुसेना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाने की तैयारी में है। 5वीं जनरेशन के इन फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप यानी प्रतिकृति को तैयार करने के लिए वायुसेना सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मांगने की तैयारी में है। अडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल की शुरुआत में इस पर काम हो सकता है। दो इंजन वाला यह एयरक्राफ्ट रेडार में आए बिना वार करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी। फिलहाल वैश्विक बाजार में मिल रहे 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट काफी महंगे हैं।

ईपीएफओ की अंशधारकों को चेताया, किसी को न दे निजी जानकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पीएफ खाताधारक सदस्यों को चेतावनी देते हुए खाते से जुड़ी अपनी निजी जानकारी किसी को भी नहीं देने का सुझाव दिया है। ईपीएफओ ने ट्वीट और वेबसाइट के जरिये यह सूचना दी है। ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा है कि संगठन कभी भी अपने सदस्योंध्अंशधारकों से आधार नंबरध्पैनध्यूएएनध्बैंक खाता नंबर जैसी निजी जानकारी देने या बैंक में कोई राशि जमा करने को नहीं कहता है। इसलिए फोन पर निजी जानकारी का खुलासा न करें और न ही फोन करने वाले के झांसे में आकर कोई राशि जमा करें। ईपीएफओ का कहना है कि फर्जीवाड़ा करने वाले ईपीएफओ कर्मचारी बनकर ईपीएफ खाताधारकों से फोन पर उनकी आधार नंबर बैंक खाता नंबर जैसी निजी जानकारी आदि मांग सकते हैं। उसका कहना है कि अगर ऐसी कोई फोन आता है तो खाताधारक इसके झांसे में न आएं।

नायडू ने की एक साथ चुनाव कराने की वकालत

» संसद में बनी थी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सहमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच गंभीर मतभेदों से अलग संसद के दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के पक्ष में विचार-विमर्श किया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ प्रथम अरूण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और सभी हितधारकों को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान की तारीफ की और कहा कि शुरुआती दिनों में आलोचकों ने इसकी प्रभावी होने पर संदेह जताया लेकिन पिछले सात दशकों में देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उपराष्ट्रपति ने संविधान में जरूरत पड़ने पर किए गए संशोधनों का भी हवाला दिया और पिछले दिनों अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच गंभीर मतभेद से परे, दोनों सदनों ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के पक्ष में चर्चा एवं विचार विमर्श किया। नायडू ने कहा कि संसदीय प्रणाली की जड़ें तब मजबूत होती हैं जब लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हों।

नवाज शरीफ की हालत चिंताजनक

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग..नवाज के नेता नवाज शरीफ की हालत चिंताजनक बनी हुयी है। पूर्व प्रधानमंत्री के निजी डाक्टर अदनान खान ने मंगलवार को कई ट्वीट कर नवाज शरीफ के सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, खून में प्लेटलेट्स की कमी और दिल के दौरे से पूर्व प्रधानमंत्री के गुर्दे सही तरीक से काम नहीं कर रहे हैं। इससे उनकी स्थिति और खराब हुई है।